SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: I want it to be formalised, Sir. Is there any rule which permits you to say 'no' when one Member ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY (Puducherry): Sir, he has already spoken on the Bill. And you have already said that the Bill is passed. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): It is already passed, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Joshi, the whole House is requesting you ... *(Interruptions)*...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF IN STATE THE MINISTRY OF PARLIAMENTRY AFFAIRS (SHRI SURESH PACHOURI): Sir, you have already said that the Bill is passed. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, he stood up after you had said that the Bill was passed. ...*(Interruptions)*...

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Sir, the Chair has to give its ruling on my request. That is my right. ...*(Interruptions)*...

श्री गांधी आजाद (उत्तर प्रदेश) **:** महोदय, बिल पास होने के बाद बोल रहे है । बिल पास हो गया ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You should have objected in the beginning. All the stages are over and the bill is passed now. Now, the Statement by the Minister.

SHRI SURESH PACHOURI: He is in the other House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. We take up the Short Duration discussion on heavy floods. Ms. Pramila Bohidar. Not present. Shri Rudra Narayan Pany.

श्री रुद्रनारायण पाणि (उडीसा) **:** महोदय, मैंने लिखकर दिया है कि श्री सुरेश भारद्वाज जी पहले बोलेंगे ।

श्री उपसभापति : आपका नाम है तो मैं बोल दिया । श्री सुरेश भारद्वाज जी । **SHORT DURATION DISCUSSION**

Heavy Floods in various parts of the country and relief measures undertaken by Government

श्री सुरेश भारद्वाज (हिमाचल प्रदेश) **:**धन्यवाद उपसभापति जी । 14 अगस्त, 2007 को आदरणीय कलराज मिश्र जी ने सारे देश में बाढ़ की स्थिति जो उत्पन्न हुई है, उसके विषय में यह चर्चा प्रारंभ की है ।

(THE VICE-CHAIRMAN, SHRI UDAY PRATAP SINGH in the Chair)

हर वर्ष मानसून सत्र का प्रारंभ होता है और इस मानसून के सत्र में हर वर्ष हम बाढ़ अथवा सूखे के बारे में चर्चा करते है । कभी इस देश में सूखा पड़ जाता है और जिसके कारण सारे देश की अर्थव्यवस्था तहस-नहस होने की कगार पर पहुंच जाती है । पीने को पानी नही मिलता है, आदमी प्यासे मर जाते है, फसलें सूख जाती हैं, अनाज खराब हो जाता है और

इसी देश में कभी इतना पानी बहता है, इतनी बाढ़ आती है कि जिसके कारण वही स्थिति जो सूखे से उत्पन्न होती है, हमारी फसलों को नुकसान होता है, किसान त्राहि-त्राहि कर उठता है । हमारा जो अर्थतंत्र है, हमारा जो Infrastructure हैं, वह समाप्तप्रायः हो जाता है और हर वर्ष हम इन विषयों पर चर्चा करते हैं ।

हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं, आज प्रातः काल जिस प्रकार एक प्रश्न भी लगा था कि हिमालय पर्वत में जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है और हमारे जो ग्लेशियर हैं, वह तापमान बढ़ने के कारण पिघलते जा रहे है और एक स्थिति यह उत्पन्न होने वाली है जब कि सारे देश में पानी पीने को भी नसीब नही होगा । आज इन्हीं हिमालय से बहने वाली नदियों से हमारे देश के प्रमुख और बड़े-बड़े राज्यों में हर वर्ष बाढ़ आती है और तबाही मचाकर के जाती है ।

बिहार देश का एक बहुत प्रमुख राज्य है, जहां से देश के बहुत बड़े-बड़े नेता हुए हैं और देश की प्रशासनिक व्यवस्था में जो अधिकारी हैं, प्रशासक हैं,उनमें से अधिकांश अधिकारी बिहार से आते हैं । वहां पर तकनीकी जानकारी रखने वाले Artisan आज सारे देश में वहां से काम करते है । पंजाब में जो हरित क्रांति हुई है, उसमें जो आज वहां पर पैदा होता है । उसको जनता तक पहुंचाने का काम बिहार के लोग करते हैं । नेपाल से जो नदियां बहती हैं और उन नदियों के कारण हर वर्ष जो बिहार के लोग करते है । नेपाल से जो नदियां बहती हैं और उन नदियों के कारण हर वर्ष जो बिहार में तबाही होती है जिसके कारण बिहार के व्यक्ति को सारे देश में काम ढूंढ़ने के लिए जाना पड़ता है । 60 वर्ष की स्वतंत्रता के पश्चात भी आज तक भारत में इस स्थिति के बारे में कोई विचार नही किया गया । नेपाल से नदी बहती है । नेपाल भारत के साथ लगता हुआ एक देश है । उसके साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध रहे है । वहां पर हम कोई डैम स्थापित करें, उस बाढ़ को रोकने के लिए कोई उपाय करें, लेकिन आज तक हम ऐसे उपाय करने में नाकामयाब रहे है । आज सबसे पहली आवश्यकता तो इस बात की है कि अगर बाढ़ की स्थिति को हमें रोकना है, तो जो नदियां हमारे हिमालय क्षेत्र से विशेष रूप से बहती है, उसपर विचार करने की आवश्यकतों है । क्योंकि ब्रह्मपुत्र हर वर्ष जो बाढ़ आती है उससे असम और नॉर्थ-ईस्ट का बहुत –सा क्षेत्र प्रभावित होता है । बिहार में, उत्तर प्रदेश में हर वर्ष बाढ़ आती है और इस वर्ष तो स्थिति यह उत्पन्न हुई है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान – राजस्थान वह प्रदेश है, जो सूखे से प्रभावित रहता है, इस वर्ष वहां भी बाढ़ के कारण इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है कि वहां बड़े-बड़े शहर पानी में डूब गए और उसके कारण वहां भारी नुकसान उठाना पड़ा है । इसी प्रकार गुजरात में हर वर्ष बाढ़ आती है, पानी बहता है और मुम्बई, जो हमारी महानगरी है, जो देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है, कहलाती है उस बुम्बई को हमारे प्रधानमंत्री जी शंघाई बनाने की दिशा में काम करना चाहते है लेकिन वह शंघाई बनने के बजाय, दिन प्रतिदिन, हर वर्ष वहां पर इतनी बाढ़ आती है, इतना पानी बहता है कि उसके कारण वहां का सारा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है, जिसके कारणा वह मुम्बई नगरी एक तरह से ठहर सी जाती है । आज तक उस पानी की व्यवस्था के लिए कुछ नही किया गया है । वहां से बहुत बड़े-बड़े राजनेता रहे हैं, सारा देश उस महानगर को ठीक स्थिति में देखना चाहता है, लेकिन उसके पानी की निकासी के लिए, वहां जो पानी आसमान से आता है, वहां पर जो नदी सी बहती है या जो समुद्र से पानी वहां ऊपर चढ़ जाता है, उसके विषय में कोई प्रॉपर काम किया जाए, वहां पर इस प्रकार का विकास सुनिश्चित किया जाए, जिससे यह स्थिति वहां पर न आए और हर वर्ष जो नुकसान उस महानगर को होता है, जिसके कारण सारे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, उसको रोकने के लिए भी सरकार को, चाहे वह महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे वह केंद्र सरकार को, उसको मिल-जुलकर काम करने की आवश्यकता है । ...(**समय की घंटी**)...

4.00 P.M.

आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, जिस प्रदेश से मैं आता हूं, वह हिमालय पर्वत की तलहटी में बसा हुआ छोटा सा शांतिप्रिय प्रदेश है । वहां पर बाढ़ के कारण तो स्थिति खराब होती ही है, लेकिन एक नए प्रकार की बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न होती है कि हिमालय पर्वत में तिब्बत से जो नदियां बहती है, विशेष रूप से सतलुज नदी जो बहती है, उसमें जो हर वर्ष बाढ़ आती है, उसके कारण बडी-बडी जल विधुत परियोजनाएं प्रभावित हो रही है । उसके विषय में चीन सरकार से बात करनी चाहिए कि किस प्रकार से सतलुज नदी पर उस बाढ़ को रोका जा सकता है । वहां से जो भारी मात्रा में सिल्ट आती है, वह हर वर्ष नही आती , कभी दो दिन में भी इतना पानी आ जाता है कि वह भारी तबाही मचा देता है । एक अन्य प्रकार की स्थिति बादल फटने की है, जिसको 'colud burst' कहते हैं । वह पानी कैसे आता है, कहां से आता है, उस पर आज तक कोई साइंटिफिक रिसर्च नही की गई है, न कोई विश्लेषण किया गया है । वहां पानी बह जाता है और सुबह के समय, जब किसी गांव में वह होता है, तो वहां पर देखा जाता है कि वह पूरा का पूरा गांव साफ हो जाता है । इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में जो पुराने पुल थे, पठानकोट को, पंजाब को हिमाचल से मिलाने वाला चक्की पुल, वह टूट गया । हिमाचल प्रदेश की अधिकांश नदियों पर जो पुल थे, वे सारे के सारे बह गए या टूट गए है और सारे प्रदेश भर में जो जल विधुत परियोजनाएं हैं, नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट, जिसमें 1500 मेगावॉट बिजली बनती है और सारे देश को बिजली मिलती है, उसमें भी सतलज में बाढ़ आने के कारण वह परियोजना काफी दिनों तक बंद करनी पडी इसके साथ- साथ बादल फटने की घटना के कारण हमारी जो एकमात्र हैरिटेज रेलवे लाइन है, जो कालका से शिमला तक जाती है, उस पर बादल फटने से एक ही रात में इतना पानी आया कि उसके कारण शिमला का नेशनल हाइवे, पूरे बॉर्डर की ओर जो पूरा आवागमन होता है, वह लगातार 34 घंटे तक बंद रहा । इसके अतिरिक्त हमारा जो घानवी का जल विधुत प्रोजेक्ट है, वहां पर बादल फटने से पूरा एक गांव, जो रात को बसा हुआ था, सुबह जब लोगों ने देखा, तो वह अपने स्थान पर नही था और आज भी वहां पर सौ से अधिक लोग बह गए अथवा कहां चले गए, उनको आज तक ढूंढ़ा नही जा सका है , इसमें केंद्र सरकार की ओर से कभी-कभी रिलीफ या रीहैबिलिटेशन की बात होती है और बडी-बडी रिलीफ मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ बनाते हैं । लेकिन उससे आज तक किसी प्रकार के रिलीफ के कारण कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ हो अथवा वहां पर जो लोग मर जाते हैं या जो नुकसान होता है, उनको कभी भी उचित समय पर मुआवजा नही मिलता है । हिमाचल प्रदेश में इस बार लगभग एक हजार करोड़ से अधिक का नुकसान जान-माल के रूप में हुआ है, पुलों के रूप में हुआ है, सड़कें पूरी की पूरी बह गयी हैं, बहुत सारे लोग बह गए हैं, हमारी सारी फसलों का नुकसान हो गया है । जो सेब की फसल वहां पर पैदा होती है, वह सड़कें टूटने के कारण मंडी तक पहुंचाई नही जा सकती, पेरिशेबल गुडस होने के कारन उसका भारी नुकसान हो रहा है । आज तक केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई भी अधिकारियों का दल उस प्रदेश में उस स्थिति की जांच के लिए नही गया है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री उदय प्रताप सिंह) : भारद्वाज जी, आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री सुरेश भारद्वाज : कभी वहां के चीफ मिनिस्टर एक हेलिकॉप्टर पर चक्कर लगा लेते है और उसके बाद यह कहा जाता है कि हम यहां पर यह भी करेंगे, वह भी करेंगे लेकिन अभी तक घानवी जहां पर पूरा का पूरा गांव बह गया है, वहां पर रीहैबिलिटेशन और रिलीफ

के लिए एक भी पैसे का काम नही हो पाया । ...(**समय की घंटी**)...माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार इस प्रकार की जो परिस्थिति आती है, जो बाढ़ की स्थिति होती है, उसके लिए जो फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट अथॉरिटी केन्द्रीय स्तर पर है, वह तुरन्त वहां जायजा लेने के लिए जाए । जो प्रदेश को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, वह उनको मुहैया करायी जाए ताकि लोगों को समय पर मुआवजा सहायता की आवश्यकता है, वह उनको मुहैया करायी जाए ताकि लोगों को समय पर मुआवजा मिल सके और प्रदेश का जो आर्थिक तंत्र है, वहां पर जो इनफ्रास्ट्रक्चर है, जो पुल हैं, सड़कें हैं, उनको बनाने के लिए काम हो सके । नॉर्थ ईस्टर्न स्टेटस की तरह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी गरीब प्रदेश हैं, उनको केन्द्र की सहायता मिलना अति आवश्यक है क्योंकि वे पर्यावरण की रक्षा करते है, जंगलों की रक्षा करते हैं, पानी वहां से बहता है । अगर उनकी रक्षा नही करेंगे तो सारे देश को नुकसान होगा । जो सारे देश के नुकसान को सहन करते है ...

उपसभाध्यक्ष (श्री उदय प्रताप सिंह) : अब आप conclude करिए ।

श्री सुरेश भारद्वाज : महोदय, कारगिल युध्द में चार में से दो परमवीर चक्र विजेता हिमाचल प्रदेश से हुए है । इसलिए सारे देश की जिम्मेदारी बनती है कि वहां के लिए प्रॉपर आर्थिक सहायता मुहैया करायी जाए । मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि तुरंत केन्द्रीय दल वहां पर भेजकर मुआवजे का जायजा लिया जाए और जो नुकसान वहां पर हुआ है, जो कि लगभग एक हजार करोड़ से अधिक का नुकसान है, उसे प्रदेश सरकार को भेजा जाए ताकि प्रदेश की बाढ़ से जो स्थिति खराब हुई है, उसको ठीक किया जा सके । आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

MS. SUSHILA TIRIYA (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to participate in the Short Duration Discussion on the flood situation, which was raised by Shri Kalraj Mishraji. Sir, several times, the Business Advisory Committee has allotted time for discussion on the flood situation prevailing in our country. Every year, we discuss the situations arising out of natural calamities like floods, cyclones, earthquakes, drought and others. But. Sir, in my opinion, there has been no permanent solution to it.

As a representative of the people of the country and as a responsible citizen of this country, we always discuss these situations of flood, cyclone, drought etc. in this House. According to my knowledge as a representative from Orissa, every year, we discuss the flood situation in our country as well as the flood situation in the State of Orissa, to which I belong. My sincere request to the Government is to find out a permanent solution. Sir, after attaining Independence, we have made a lot of progress in these sixty years, and, our scientists have a lot of achievements to their credit, why don't you think of a permanent solution for this kind of natural calamity, which badly affects our country and its agriculture, and, which causes loss of lot of lives in the country. Sir, basically, agriculture is the heart of this country. According to my thinking, in Orissa, we do not have a lot of employments and a lot of creamy layer of the society. We have people who mostly depend on agriculture. Every year this kind of floods damage a lot of agricultural land. Agriculture suffers means the economy of the country suffers. So, if some solution, some plan, some project or some scientific solution from our State Government is pending with the Central Government, my sincere request is to discuss the same and come out with certain progressive solution for my State. This year, U.R, Karnataka, Bihar, Maharashtra, Andhra Pradesh, Orissa, West Bengal and Assam are mostly affected States

according to the newspaper and television reports. The Central Government has released an amount of Rs. 1,292 crores for these States. Specifically, for Orissa, for the period 2005-10, there is a proposal to release Rs. 1599.16 crores. For 2005-06, the Central Government has already given an amount of Rs. 301.54 crores. My point here is that those States are mostly affected in the current flood situation. But, the relief given is not sufficient in quantity. We are concerned about the relief. Sometimes the State Government throws some responsibility on the Central Government saying that the Central Government is not releasing that much of amount that they have asked for. They are not even able to give the relief to the affected areas. Every year, Mahanadi and Kathajodi, which are basically in central Orissa, affect the area a lot. Even if small quantity of rain falls, Mahanadi and Kathajodi rivers overflow causing floods. So, this area is affected a lot every year. People in this area have been suffering since long. Similarly, north Orissa is affected by Baitarani, Shubarnrakha and Budhabalang and south and west Orissa is affected by Bansdhara and Nagabali. In the Shubarnrakha and Budhabalang area, around 11 lakh people have been affected. Forty-three blocks, 11 districts and 62,000 people have been affected during the current year. The Revenue Minister from our State says that 196 makeshift kitchens have been opened to provide food for 62,000 affected people to give them some relief. My only suggestion is this. During the time of Shri Vinayak Acharya as Chief Minister, Dr. K.L. Rao was a scientist and also the then Irrigation Minister. He did a very good research and gave a suggestion on how to control the flood situation in Orissa. Now, the Orissa Government along with the Central Government has found some permanent solution and set up a project called the Geo Hydro Technique Project at Digha. If flood situation is controlled by the Geo Hydro Technique Project in Orissa, why don't the Central Government also go in for the same measure to deal with such situations? This is my suggestion. My other point is this. Lots of livestock and human beings, some belonging to Below the Poverty Line, have suffered in the floods in Orissa. Orissa is a poor State. My point here is that if we resort to *ad hoc* measures every year, it cannot be a permanent solution. We only go on discussing it. We only ask the Central Government and the State Governments to give them some relief. This will continue for a long time. What should we then do? Here we have to discuss issues. Sushila Tiriya will participate from Orissa and others will participate from respective affected States. This will continue in Parliament and the State Assemblies. So my point is that this is the right time and the right situation to face the challenge of flood situation in the country. How to live with the floods; how to overcome this situation; and how to have a permanent solution for the floods in the country? So, my point here is that we should not go on discussing it again and again. I am emphasising this point. We have made developments in different fields, especially science. Why don't we encourage the scientists to conduct research and bring in proper measures to control this problem?

Orissa is a State of rivers. Lots of rivers surround Orissa. A time will come when Orissa will be washed out; according to the Census, population of Orissa will reduce and livestock will also reduce; and if the Central Government or the State Governments do some development work in that state, it will be meaningless. My request is to rebuild the embankment. Some of my colleagues have said that there are some weak points and from those weak points water will come out. When rain comes, it will damage the embankment and water will leak from that embankment and

it will flood the region there. This is not my point that only weak points have to be repaired for the time being. Next year again we will face this kind of problem.

At Mahanadi basin, some research has been done. The Government of Orissa has got Mahanadi Basin Development Plan. It has been sent to the Central Government. If that is prepared and that is satisfactory, implement it to solve the problem of flood situation in Orissa.

My last point is, recently Rayagada is facing severe floods. There is a river valley which is washed out. The only remains of it include a defence bridge. Why don't we allow the people to use that bridge? The defence personnel are using that. Why don't we give them instructions to use that bridge for public purpose for the time being to meet the problems of the area until the damaged bridge is repaired?

Lastly, I can say one thing that we discuss this issue and make some points. This is the situation when we should not do politics only. The engineers and contractors should not do politics during the prevailing flood situation of the country. We should not play with the lives of the affected people, the poor people, the tribal people, the SC/ST people, the people living along river embankment, etc. We should stop playing politics on the sufferings of these affected people as we celebrate the sixty years of Independence. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्री उदय प्रताप सिंह) : श्री गांधी आजाद । आपके पास मात्र तीन मिनट हैं ।

श्री गांधी आज़ाद (उत्तर प्रदेश) **:** गांधी के साथ ही अन्याय ।

उपसभाध्यक्ष (श्री उदय प्रताप सिंह) : इसमें जो लिखा हुआ है, वही बोल रहा हूं ।

श्री गांधी आज़ाद : धन्यवाद महोदय । आज देश में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल , महाराष्ट्र, उडीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल दस प्रदेश बाढ़ से प्रभावित हैं ।

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश) **:** हिमाचल प्रदेश भी है ।

श्री गांधी आज़ाद : उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, बस्ती, बहराइच, महाराजगंज, बाराबंकी, पीलीभीत, फैजाबाद, संत कबीर नगर, सिध्दार्थ नगर, शाहजहांपुर, बरेली, खीरी, गोंडा, रामपुर, कोसी नगर, उन्नाव, सीतापुर, एटा, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया बाइस जिले बाढ़ से प्रभावित हैं । प्रभावित गांवों की संख्या लगभग तीन हजार है । आबादी लगभग तीस से चालीस लाख, प्रभावित फसल क्षेत्र तीस से पैंतीस लाख हेक्टेयर, क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या लगभग सवा दो लाख, जन हानि क्षति 170, मारे गए पशुओं की संख्या 141 है ।

महोदय, राज्य सरकार द्वारा सूचित अनुमानित क्षति 1722.80 करोड़ है । हमारी नेता और देश की मुखिया बहिन कुमारी मायावती जी ने केंद्र सरकार से सहयोग के रूप में 2200 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा केवल 235.10 करोड़ रुपए दिए गए । लगभग 1965 करोड़ की हमारी डिमांड है । सरकार को चाहिए कि राहत के रूप में उत्तर प्रदेश को पैसा दे ताकि वहां के लोगों को संसाधन मुहैया कराकर बाढ़ से मुकाबला किया जा सके । उत्तर प्रदेश में सिंचाई दुरुस्त करने के लिए सिंचाई विभाग में बाढ़ प्रखण्ड की भी व्यवस्था है, लेकिन धन के अभाव में काम थोड़ा शिथिल पड़ गया है । इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि जल्द से जल्द 1965 करोड़ रुपए देकर

उत्तर प्रदेश को राहत देने का काम करें । साथ ही साथ बिहार के 19 जिले प्रभावित है । इसमें प्रभावित गांवो की संख्या 6000 से 7000 तक है । प्रभावित आबादी 1.5 करोड़ है, प्रभावित फसल क्षेत्र लगभग 12 लाख हेक्टेयर है, क्षतिग्रस्त मकान की संख्या 1,30,000 है, जन हानि 161 करोड़, पशु हानि 100 करोड़ है । राज्य सरकार द्वारा अनुमानित 15.70 करोड़ है । इस तरह से वहां पर बाढ़ क्षेत्र की हालत बहुत खराब है । मैंने खुद वहां, पर बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी होने के नाते बख्तियारपुर क्षेत्र में अपने साथियों के सहयोग से 500 लोगों, जिनका कटाव में घर बह गया था, उनको चावल, चूड़ा, गुड़ पोलिथीन, सिलाई और माचिस आदि देने की व्यवस्था की थी । इस प्रकार से बाढ़ प्रबंधन में सहयोग करने का काम किया था । मेरा सुझाव है कि जैसे काफी समय से मिट्टी का कटाव हो जाने के कारण नदियों की गहराई कम हो गई है,पानी का बहाव कम हो जाता है ...। इसलिए पानी फैल कर बाढ़ को ज्यादा प्रभावित करता है । इसलिए हमारा सुझाव है कि नदियों की खुदाई करके, उसकी गहराई और पानी के flow, पानी की धारा को बढ़ाने का काम किया जाए और नदियों के किनारे बाँध बना कर बड़े-बड़े डैम बनाए जाए और उन पर वृक्षारोपण कर दिया जाए, तो इससे बाढ़ कम प्रभावित होगी । जहाँ ज्यादा जगह है, वहाँ झीलनुमा, बड़े-बड़े तालाबनुमा बना कर, उन पर डैम बना कर वहाँ जलाशय बनाया जाए, मछलीपालन किया जाए और सारी चीजें की जाए । वहाँ से drainage निकाल कर समुचित सिंचाई की भी व्यवस्था की जाए ।

नदियाँ एक तरफ कटाव करती हैं, तो दूसरी तरफ पटाव करती है । अगर कटाव वाले क्षेत्र को रोकने की व्यवस्था की जाए और पटाव वाले क्षेत्र को गहरा किया जाए, तो शायद इस बाढ़ क्षेत्र से बचा जा सकता है ।

मेरा सुझाव है कि सरकार की नदियों को जोड़ने की जो स्कीम थी, अगर उसको क्रियान्वित किया जाए, तो पानी का सदुपयोग भी किया जा सकता है । बाढ़ वाले क्षेत्र का पानी सूखा वाले क्षेत्र से जोड़ा जा सकता है । मैं समझता हूँ कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी और खास तौर से उत्तर प्रदेश को बाढ़ पैकेज देने का काम जरूर करेगी । इसी प्रत्याशा में आपका धन्यवाद ।

उपसभाध्यक्ष (श्री उदय प्रताप सिंह) : श्री नन्द किशोर यादव, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री नन्द किशोर यादव (उत्तर प्रदेश) **:** धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी । आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद ।

उपसभाध्यक्ष जी, हर साल मानसून सत्र में इस सदन में बाढ़ पर चर्चा होती है और इस बार भी हम यहाँ बाढ़ पर चर्चा कर रहे है । आदरणीय कलराज मिश्र जी ने जब यह चर्चा आरम्भ की, तो उन्होंने विस्तार से बताया कि इस साल बाढ़ में बहुत अधिक क्षति, चाहे जन हानि समझ लीजिए, चाहे पशु हानि, चाहे फसलों का नुकसान हुआ । गृह मंत्रालय के द्वारा एक पुस्तिका भी हम लोगों को प्राप्त हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि 10 प्रान्तों में बाढ़ आई हैं । कुछ सदस्य इसे 12 बता रहे है, लेकिन गृह मंत्रालय ने कहा है कि 10 प्रान्तों में बाढ़ आई है । उससे ज्यादा नुकसान हुआ है फसलों का, मकानों का और सार्वजनिक सम्पत्ति का । जो नुकसान हुआ है, उसकी अनुमानित क्षति 3,213.41 करोड़ है । पूरे देश में 217 जिले प्रभावित हुए हैं ।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हम पिछले 60 वर्षो से लगातार इस तरह की प्राकृतिक आपदा को झेल रहे हैं और इन 60 वर्षो में हम इसका कोई प्रबन्धन नही कर पाएं । मैं जिस प्रदेश

से आया हूँ, वहाँ 22 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और करीब 25 जिले ऐसे हैं, जो सूखे से प्रभावित है । मैं उत्तर प्रदेश के जनपद आज़मगढ़ का रहने वाला हूँ, वहाँ जनपद का जो उत्तरी क्षेत्र है, वह बाढ़ से प्रभावित है और उस जनपद का जो दक्षिणी क्षेत्र है, वह सूखे से प्रभावित है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस साल सामान्य से कम वर्षा हुई, लेकिन कुछ क्षेत्र है, वह सूखे से प्रभावित है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस साल सामान्य से कम वर्षा हुई, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ गई । खासकर जिधर से घाघरा निकली हुई थी, चाहे आज़मगढ़ जनपद हो, मऊ हो, देवरिया हो, घाघरा के किनारे जो गाँव बसे थे, उनमें बाढ़ आ गई और हर साल आती है । यह मानसून की वर्षा से नही होता है । नेपाली नदियों के या नेपाल से जो पानी आता है, उसके कारण हर साल पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र प्रभावित होता है । हमारे यहाँ पिछले वर्ष इसी घाघरा की बाढ़ से देवारा क्षेत्र, जो नदी के बीच पड़ जाता है, उसके दो गाँव पिछली बाढ़ में समाप्त हो गए ।

मेरे पास समय नही है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो मानसून का पानी है या बाढ़ का पानी है, हमें गम्भीरता से इसका प्रबन्धन करने की आवश्यकता है ।क्योंकि अभी 3-4 महीने बाद जैसे ही बरसात का मौसम खत्म होगा, जाड़ा आएगा । जाड़े के बाद जब गरमी का मौसम आएगा, तो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहाँ का मैं रहने वाला हूँ **...(समय की घंटी)...** वहाँ पानी का जो जल-स्तर है, वह बहुत तेजी से नीचे चला जा रहा है । जो छोटी मशीनें हैं । जो हाथ से चलाई जाती है और जो इंडिया मां की है हम्ड पम्प लगाते है वे पानी छोड़ देते है । किसान जो नलकूप लगाता है, उससे पानी नही निकलता है । मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि बाढ़ का प्रबन्ध होना चाहिए । इससे हमारी फसलों का नुकसान हो रहा है, पशुओं का नुकसान हो रहा है, जन-हानि हो रही है, देश के आर्थिक विकास में परेशानी खडी हो रही है । हमें इस तरह का प्रयास करना चाहिए कि **...(समय की घंटी)....** जो मानसून का पानी है, इसको ज्यादा-से-ज्यादा हम जमीन के अन्दर ले जाने का काम करें । मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले, केवल एक मिनट में एक-दो बातें और कहना चाहता हूँ, सर ।

अभी गांधी आज़ाद जी बोल रहे थे । उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार है । मैं आलोचना नही करना चाहता हूँ । जिस समय बाढ़ आई थी, उस समय सरकार बन गई थी । हर साल बाढ़ के समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो जिला प्रशासन होता है, बाढ़ प्रबंधन का काम करता है, जन प्रतिनिधियों को बुलाने का काम करता है, बांधों को दिखवाने का काम भी करता है । **...(समय की घंटी)....** तथा जो तटबंध टूटे रहते है उनको ठीक करवाने का काम भी करता है। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI UDAY PRATAP SINGH): Please conclude.
...(Interrutpions)...

श्री नन्द किशोर यादव : लेकिन वर्तमान सरकार ने इस तरफ ध्यान नही दिया । हम प्राकृतिक आपदा को रोक तो नही सकते थे,लेकिन जो भयंकर क्षति हुई है,**...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री उदय प्रताप सिंह) : अब आप कंक्लूड करिए**...(व्यवधान)...** Please conclude. ...(Interrutpions)...

श्री नन्द किशोर यादव : हम उसको रोकने का काम करते । आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपसभाध्यक्ष (श्री उदय प्रताप सिंह) : श्री महेन्द्र साहनी ।

श्री महेन्द्र साहनी (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, बाढ़ के विषय में बात यह है कि जब हम लोग यहाँ नही रहे होंगे या यह हाउस नही रहा होगा, उस वक्त से ही बाढ़ की विभीषिका इस देश में है । मैं बिहार से आता हूँ । मैं वहाँ के मुजफ्फरपुर जिला से आता हूँ, जहाँ से बहुत ही कम दूरी पर नेपाल की सीमा है । भारत सरकार के कानून में है कि नदी पर पूरा अधिकार उनका है, पहाड़ पर पूरा अधिकार उनका है, जंगल पर पूरा अधिकार उनका है । यह बात समझ में नही आती है । पिछले 70 वर्षो से तो कम-से-कम हम देख रहे है । जाने दीजिए, अगर हम आजाद भारत की ही बात करें, तो पिछले 60 वर्षो से हम यह देख रहे है । यह कैसी विड़म्बना है कि कहीं से भी सोच नही है कि हर साल लाखों हेक्टेयर जमीन दीजिए, अगर हम आजाद भारत की ही बात करें, तो पिछले 60 वर्षो से हम यह देख रहे है । यह कैसी विड़म्बना है कि कहीं से भी सोच नही है कि हर साल लाखों हेक्टेयर जमीन समाप्त हो जाती है, हजारों आदमी मर जाते है, इसमे काम करने वाले नाविक मरते हैं, मछुआरे जो इसमें काम करते हैं, जो आदमी को इधर से उधर ढ़ोते हैं, वे मरते हैं, लेकिन आज जब आप कहते हैं कि हम नदियों के, जंगल के और पहाड़ के मालिक हैं, तो फिर आपको सोचना चाहिए । कम-से-कम बिहार सरकार के जो अपने दायरे होंगे, उस दायरे में वह कर रही होगी, लेकिन खासकर केन्द्रीय सरकार को इस बात को सोचना चाहिए था, जो आज तक नही सोचा गया । यह बहुत ही दुखद प्रसंग है । इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह कहना चाहता हूँ और मैं यह जवाब जनता के बीच देने के लिए आग्रह करता हूँ कि वह बताए कि पिछले 60 वर्षो से इसमें क्यों नही सोचा गया । गंडक नदी को हम लोगों ने बाँध दिया, तो वह बहुत ही कंट्रोल में है । तब क्या हम घाघरा को नही बाँध सकते, क्या हम बागमती को नही बाँध सकते, क्या हम लखनदेई को नही बाँध सकते, क्या हम बाया को नही बाँध सकते, क्या हम कमला को नही बाँध सकते और क्या हम कोंसी को नही बाँध सकते? यह कैसी विड़म्बना है? किसी सोच में कहाँ कमी है कि आज तक इस विषय में नही सोचा गया? मैं आग्रह करता हूं कि भारत सरकार ने बिहारवासियों के लिए, जो पिछड़ा बिहार है, उस को कहा जाता है कि पिछड़ा स्टेट है, उस के बारे में उस ने नही सोचा । उस ने बाढ़ पीडितों को रुलाया है । मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि, "बिहार के बाढ़ पिडितों को रुलाए, उसे केन्द्रीय सरकार कहते हैं।" "बिहार के बाढ़ पीडितों को 60 वर्ष से रुलाए उसे केन्द्रीय सरकार कहते है और केन्द्रीय सरकार को समर्थ दे, सहलाए, उसे पार्टनर महान कहते हैं ।" केन्द्रीय सरकार को सहलाए, समर्थन दे रहे, पार्टनर महान कहलाए, इन पार्टनर महान को और पार्टनर महान को भीतर-भीतर तरसाए और अपने आप को आगे बढ़ाए, उसे यू0पी0ए0 सरकार कहते है । जय हिंद ।

उपसभाध्यक्ष (श्री उदय प्रताप सिंह) : श्री संजय राउत ।

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र) : धन्यवाद सर, आप ने मुझे मौका दिया । सर, कलराज मिश्र जी को बाढ़ की स्थिति पर चर्चा शुरू किए आज 10-12 दिन हो गए, लेकिन सदन को टाइम नही मिला । हम 14 तारीख से इंतजार कर रहे हैं कि यह चर्चा पुनः शुरू होगी , लेकिन मुझे लगता है कि देश की बहुत गंभीर स्थिति पर चर्चा करने के लिए न सरकार के पास टाइम है,न हमारे पास टाइम है ।

महोदय, कहीं भी 20-25 लोग मर जाते है, विस्फोट होता है, बहुत गंभीर बात है, उस के लिए सदन की कार्यवाही रोक दी जाती है । लेकिन देश में बाढ़ से, तूफान से हजारों लोग मरते हैं, चर्चा के लिए टाइम नही है । महोदय, बिहार में 2 हजार से ज्यादा लोग मर गए, महाराष्ट्र में 500 लोग मर गए, लेकिन यहां चर्चा नही हुई । आज भी देश के बड़े हिस्से

में बाढ़ से तबाही मची हुई है । हालांकि पानी कम हुआ है, लेकिन जनता बेहाल है । महोदय, इस देश में कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा आता है, कभी सुनामी आता है, कभी भूकंप आता है और एक चक्रव्यूह की स्थिति पैदा होती है । इस बार भी बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, केरल में, आंध्र प्रदेश में बाढ़ से तबाही मची है । पूरे देश में यह स्थिति है । मैं महाराष्ट्र से आया हूं । मुंबई की बात बहुत से वक्ताओं ने की, भारद्वाज जी ने की । इस बार भी मुंबई में भारी बारिश हुई, लेकिन महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में बाढ़ से कहर मच गया । तूफानी बारिश से एक महीने में 400 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गयी, 50 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हुए और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 75 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा । विदर्भ में सब से ज्यादा तबाही अमरावती क्षेत्र में हुई । वहां तो सिर्फ आसमान से बिजली गिरने से 110 लोग मारे गए । बारिश से सड़कों का नुकसान हुआ जिन्हें बनाने के लिए कम-से-कम 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी ।

महोदय, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है । प्रधान मंत्री जी बार-बार मुंबई को शंघाई बनाने की बात करते है, लेकिन मुंबई शहर 7 द्वीपों से बना है और मामूली सी वर्ष से इस शहर के लिए एक संकट की स्थिति पैदा हो जाती है, मामूली सी वर्षा इस शहर के लिए काल बनकर आती है और हजारों निर्दोष लोगों की बलि लेकर शांत होती है । सर, भारी बारिश का बोझ उठाने में मुंबई की मौजूदा ड्रेन सिस्टम सक्षम नही है । केन्द्र सरकार ने ब्रेनस्ट्रोम योजना की बात की है, जिसके लिए लगभग 1400 करोड़ की योजना मंजूर की है और मुझे लगता है कि कल या परसो प्रधान मंत्री जी वहां जाकर पहली इन्सटालमेंट, जो 400 करोड़ की है, वह देने वाले हैं,लेकिन यह योजना पूरी होने के लिए 15 साल लगने वाले है और तब तक यह बात चिंता की स्थिति पैदा करेगी ।

महोदय, जो हम टी.वी. पर देख रहे थे, सबसे बुरा हाल बिहार का था । वहां चार-पांच दिन तक लोग पानी में थे, भूखे थे, बेसहारा थे, ...(**व्यवधान**)... मैं टी.वी. पर देख रहा था । क्या यह स्थिति नही हैं?

उपसभाध्यक्ष (श्री उदय प्रताप सिंह) : प्लीज़, प्लीज़ । संजय राउत जी, Please address the chair.

श्री संजय राउत : सर, ये डिस्टर्ब करते है ।इनको मालूम नही है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री उदय प्रताप सिंह) : चलिए, बोलिए । आपका समय वैसे ही कम है ।

श्री संजय राउत : सर, बारिश होती है, तूफान और बाढ़ भी आती है, लोगों के घर-बार बारिश में बह जाते है, लेकिन तूफानी बारिश में सबसे पहले सरकार बह जाती है, बाद में जनता डूब जाती है । सरकारी मशीनरी का यह फेल्युअर है । फिर सरकार स्टेट की हो या सेंटर की हो, देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ बार-बार क्यों आती है और बाढ़ से निपटने के लिए हमारे पास क्या योजनाएं है?

महोदय, मैं दो बातें करूंगा – डिजास्टर मैनेजमेंट की और दूसरी बात ग्लोबल वार्मिंग की । डिजास्टार मैनेजमेंट की बात बार-बार होती है, लेकिन आपदा नियंत्रण की सब योजनाएं फेल हो जाती हैं, जब ऐसा संकट आता है । सैकड़ों व्यक्ति काल के गाल में इसलिए समा जाते है, क्योंकि आपदा नियंत्रण की समुचित व्यवस्था नही है । यह भी सच है कि प्रकृति पर किसी का नियंत्रण नही चलता, फिर भी संकट की घडी में सरकारी यंत्रणों का भी बाजा बज जाता है । इस समय सरकार भी अदृश्य हो जाती है । क्या जनता को उसके हाल पर छोड़

दिया जाना उचित है? अतिवृष्टि और बाढ़ का ताडंव सिर्फ गरीब ही झेलते है, कोई नेता इसकी चपेटा में नही आता है । कुछ राज्यों में हर साल भारी बाढ़ आती है, परन्तु बाढ़ नियंत्रण योजना धूल खाती पड़ती है । आपदा नियंत्रण या क्राइसेस मैनेजमेंट के लिए प्रशिक्षण देने के लिए कौन सी व्यवस्था है? यह सरकार नही बता सकती । जब हालात बिगड़ जाते है, तो सरकार और प्रशासन में कोई समन्वय नही होता ।

सर, बाढ़ नेपाल में आती है, बंगलादेश में आती है, वहां की नदियों पर तूफान आता है और उससे तबाही उत्तर प्रदेश में होती है, बिहार में होती है । नेपाल से आने वाली नदियों पर बांध बनाने की योजना है । अभी-अभी कुछ काम भी शुरू हो गया है, लेकिन कोई नही जानता कि इस योजना के पूरे होने में कितने दशक और लगेंगे? आज यह कोई नही जानता कि इस योजना के पूरे होने में कितने दशक और लगेंगे? आज यह कोई नही कह सकता । देश में इस वर्ष भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 33 अरब रुपए से ज्यादा नुकसान हो गया है । मैंने हाल में एक रिसर्च पढ़ी, उसके अनुसार देश में हर साल औसतन 1,250 लोग बाढ़ से मरते है और 75,000 से ज्यादा मकान बाढ़ और तूफानों से गिरते हैं । संपत्ति की हानि भी कम नही होती । हर साल 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति बाढ़ में नष्ट होती है और सरकार हतप्रभ हो यह सब देखती है । **...(समय की घंटी)...**

सर, थोडी सी बात है । सर, आप हमारे चेयरमैन हैं, आप तो घंटी मत बजाओ । **...(व्यवधान)...** सर, हमारे देश में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम शुरु है । पिछले पचास वर्षो में कुल मिलाकर 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके है, लेकिन हमारे देश में बाढ़ जिस बड़े पैमाने पर आती है, उस हिसाब से कुछ काम बाकी है ।

सर, आज देश में और पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है । ऐसा लगता है कि प्रकृति भी हमसे बदला ले रही है । हमने प्रकृति के साथ अन्याय किया है, पेड़ काटे हैं और काटने के बाद नए पेड़ नही लगाए हैं । इस तरह पर्यावरण के साथ भी खिलवाड़ हुआ है । इसका परिणाम यह है कि जहां पानी नही बरसता था, वहां इतना पानी बरसा है कि सबको डुबा रहा है । कहीं पानी ज्यादा बरसा है और कहीं सूखा पड़ रहा है । इससे मुसीबतें बढ़ रही है। प्रकृति के इस प्रकोप से हमको लड़ना होगा और हम सभी को, सरकार को इस विषय को गंभीरता से देखना होगा । धन्यवाद ।

श्रीमती विप्लव ठाकुर : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपने बाढ़ की समस्या पर बोलने के लिए मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं तो यह कहूंगी कि 14 अगस्त को कलराज मिश्र जी ने यह चर्चा शुरु की थी, जो आज पूरी होने जा रही है । वैसे तो यह अत्यंत गंभीर समस्या थी और इसे सदन को बहुत पहले लेना चाहिए था, लेकिन सदन के पास और ही इश्यू थे, जिससे इस गंभीर विषय पर विचार करने का समय नही मिला ।

मैं ज्यादा नही कहना चाहती, क्योंकि पूरे देश में बाढ़ का प्रकोप हुआ है, बहुत प्रदेश इसमें क्षतिग्रस्त हुए है । होम मिनिस्ट्री ने जो एक रिपोर्ट दी है, मैं पहले तो वह ठीक करना चाहती हूं, उन्होंने 10 प्रान्त दिए है, हिमाचल प्रदेश में भी सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, मैं चाहूंगी की उसको भी उनकी रिपोर्ट में रखा जाए, उसको इससे वंचित न किया जाए ।

सबसे बडी बात है कि हिमाचल में बारिशें पहले भी होती हैं, नुकसान होता है, लेकिन वहां प्रकृति का एक नया खेल शुरू हो गया बादल फटने का । कभी हमने 1980 में यह सुना

था कि किन्नौर में बादल फटा, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन अब तो हिमालय में हर वर्ष बादल फटने का खेल प्रकृति कर रही है। यहां पर मैंने अपने साइंस एंड टैक्नोलॉजी के मंत्री श्री कपिल सिब्बल जी से एक सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछा था कि जिस तरह से आप समुद्र में तूफान आने के बारे में लोगों को पहले से आगाह कर देते है, क्या कोई ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट आप हिमाचल में लगाने जा रहे है जिससे कि बादल फटने का पहले पता लग जाए?

हम गांव तो नही उठा सकते, लेकिन लोगों को तो वहां से उठाकर दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। इस बार भी हमारे यहां बरसात की वजह से 90 से ऊपर लोगों की जानें गई है। यह कोई छोटी बात नही है। अगर दरिया से या पानी बरसने से बाढ़ आती है तो उसे समझा जा सकता है। जिस तरह से सभी ने कहा कि इस पर पूरे तौर से एक डिस्कशन होनी चाहिए और एक ऐसी योजना बनाई जानी चाहिए कि इस बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है, चाहे वह बंगाल हो, चाहे वह असम हो ,चाहे वह उडीसा हो, चाहे बिहार हो, सबके लिए ऐसा एक प्रोग्राम बनाना चाहिए। जैसे एक विचार आया था सभी नदियों को इकट्ठा करने का, उसी तरह की सोच इस बारे में भी जरूर आनी चाहिए और उसका कोई साइंटिफिक उपाय जरूर करना चाहिए।

हिमाचल में जो नुकसान हुआ है, उपसभाध्यक्ष जी, वह 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर का हुआ है और भारत सरकार ने पहली किस्त भेजी है, लेकिन दूसरी किस्त अभी तक नही भेजी। हमारा प्रदेश एक गरीब प्रदेश है, हमारे यहां साधन नही है, हमारे पास इतने रिसोर्सिस नही है कि सरकार अपनी तरफ से लोगों को दे सके। ठीक हैं, पुलों के लिए पैसा आ जाता है, सड़को के लिए पैसा आ जाता है, लेकिन उपसभाध्यक्ष जी, जिस किसान की फसल गई है बरसात की वजह से, जिसके पास आज मक्की नही रह गई, पूरी फसल उजड़ गई है, धान नही रहा, उस किसान को हम क्या देते हैं? केन्द्र सरकार रिलीफ मेन्युअल में चेंज क्यों नही करती ? उसमें चेंज क्यों नही की जाती, ताकि उन किसानों को भी मुआवजा दिया जाए। आज हमारा चक्की का पुल टूट गया है, मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं इनसे कहना चाहती हूं कि कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट उसके लिए किया जाना चाहिए, ताकि पठानकोट से, हमारी जो जीवन रेखा है, उसमें अल्टरनेट उसके लिए किया जाना चाहिए, ताकि पठानकोट से, हमारी जो जीवन रेखा है, उसमें अल्टरनेट ढ़ंग से ट्रेफिक जा सके। इसी तरह से मैं यह कहना चाहूंगी हिमाचल के लिए वहां पर मशीनरी होनी चाहिए।

सबसे बडी बात जो आ रही है, वह भूमि के कटाव की आ रही है, भूमि के कटाव के लिए कहीं कोई साधन नही रखे जाते। किसान की भूमि पूरी तरह बह जाती है, बेचारा इकट्ठा करता है, उसके पास इतना पैसा नही होता कि वह उस पर डंगे लगा सके, वह उस पर कुछ बना सके, उस भूमि को सुधार सके। तभी तो वह कर्ज के बोझ से दब जाता है और जो आत्महत्याओं की घटनाएं सुनने में आ रही है, ये इसी लिए होती है। प्राकृतिक आपदा के वक्त किसान का पूरा ध्यान रखना चाहिए, यह मैं कहना चाहती हूं और सबसे बडी बात मैं यह कहना चाहूंगी आपसे कि इसके लिए जो डंगे हैं और जो पुलों वगैरह की क्षति हुई है, उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए और भारत सरकार की सरकारी टीम तब जाती है जब बरसात के दो-तीन महीने हो चुके होते है। बरसात के दो-तीन महीने बाद यहां से सरकारी टीम जाएगी, वह जाकर जायज़ा करेगी, फिर यहां आकर रिपोर्ट देगी, तब पैसा आएगा और तब तक जो बिगड़ना होता है, जो खत्म होना होता है, वह खत्म हो जाता है। उपसभाध्यक्ष जी, सिर्फ लगान माफ करके किसान का भला नही हो सकता, उसको मुआवजा देना ही चाहिए, वह मेन्युअल में रखना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री तारिक अनवर (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष जी, असम से लेकर महाराष्ट्र तक, इस देश में शायद ही कोई ऐसा प्रदेश रह गया है, जिसने बाढ़ की पीड़ा न भुगती हो, हर प्रदेश आज इससे प्रभावित है और इसको झेल रहा है। मैं इस सदन का ध्यान खास तौर पर बिहार की तरफ ले जाना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि बाढ़, बिहार का मुकद्दर बन गई है। शायद ही कोई ऐसा वर्ष होता है, जब बिहार में बाढ़ न आती हो, हर वर्ष वही कहानी, लोगों की वही पीड़ा, उसी तरह किसानों का नुकसान, जानवरों का नुकसान, हर तरह से बिहार, खास तौर से उत्तर बिहार का जो हमारा इलाका है, वहां के बारे में यह कहने में मुझे जरा भी संकोच नही है कि वहां की स्थिति सबसे दयनीय है। अभी तक की जो सूचना है, उसके अनुसार 500 से अधिक लोग बाढ़ में डूबकर मर चुके है, 2 करोड़ से अधिक आबादी, बाढ़ से प्रभावित है, लगभग 10,000 गांव इससे पीडित हैं। हमारे यहां 225 ब्लॉक और 20 जिले इस बाढ़ की चपेट में है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 15 लाख, 88 हजार हैक्टेयर की फसल अब तक बाढ़ की वजह से बरबाद हो चुकी है, 4 लाख घर पानी में डूब चुके है और लगभग समाप्त हो चुके है। यह सारी स्थिति आज बिहार के अंदर है। वहां 10 लाख से ज्यादा लोग बांध पर, तटबंध पर, रेलवे ट्रैक पर, सड़क के किनारे किसी तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहे है। ये जो चीजें है, इनके बारे में जैसे और लोगों ने भी सुझाव दिए, मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार को बहुत ही गंभीरता से इन चीजों को लेना चाहिए, राज्य सरकार के ऊपर छोड़ना नही चाहिए। राज्य सरकार के पास जो साधन हैं, वे सीमित साधन हैं और जैसे लोगों ने कहा कि अगर हमें बाढ़ को रोकना है, तो खास तौर पर बिहार की बाढ़ के बारे में, नेपाल से जो नदियां आती है, वे बिहार की बाढ़ को प्रभावित करती है, इसलिए उनको रोकने और बांधने की जरूरत है इसके लिए केन्द्र सरकार को पहल करनी चाहिए। हम लोग इस बात को लगातार कहते आए हैं, कई वर्षो से यह सवाल उठ रहा है, लेकिन उस दिशा में कोई पहल नही हो रही है।

दूसरा, हमारे यहां बाढ़ आने का मुख्य कारण यह भी है कि हमारे यहां जो तटबंध बना है – चाहे वह गंगा के किनारे हो, चाहे वह महानंदा के किनारे हो, चाहे गंडक के किनारे हो, हमारे यहां जितनी भी नदियां निकलती हैं, उस तटबंध का रख-रखाव ठीक नही है, कई वर्षो से उसकी देखभाल नही हो रही है और अगर उसकी देखभाल हो भी रही है, तो इस तरह से हो रही है कि जब बाढ़ आने लगती है,जब बाढ़ करीब होती है, जब नदियों में पानी आ जाता है, तब flood protection का काम शुरू होता है और उसकी वजह से जो ठेकेदार हैं और प्रशासन के लोग हैं, उनकी मिली भगत से वह पैसा सिर्फ पानी में बहता है, उसकी सिर्फ लूट होती है और अरबों रुपए का जो हमारा साधन है, वह पानी में बह जाता है। ये जो बातें हैं, इन पर किस तरह से निगरानी होनी चाहिए, कैसे इनकी देखभाल होनी चाहिए, इस पर हमे सोचना चाहिए। अगर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार की सहायता करती है। तो उसको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो पैसा या साधन हम राज्य सरकार को मुहैया कर रहे हैं, वह ठीक ढ़ंग से लोगों तक पहुंच रहा है या नही पहुंच रहा है। लोगों तक उसका लाभ पहुंच रहा है या नही, वह flood protection के काम में लग रहा है या नही, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, किसानों का जो नुकसान हुआ है, यह सही है कि किसान आज बिल्कुल दरिद्र हो गया है, क्योंकि सारी फसल डूब चुकी है, अब उसके पास जीने का कोई साधन

नही रह गया है और मैं समझता हूं कि इसमें राजनीति की कोई बात नही है, सभी राजनीतिक दलों को इस मामले पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि यह मामला आम जनता से जुड़ा है । आम किसानो से जुड़ा है । किसानों की जो दरिद्र स्थिति है, उससे उनको कैसे उबारा जाए, इस बात पर जरूर केन्द्र सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसके लिए कोशिश करनी चाहिए । वैसे तो अभी तक जो नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति कैसे होगी, हालांकि हम नही समझते कि इसकी पूर्ति हो सकती है... लेकिन कम से कम उनके बाल-बच्चों की कैसे जान बचे, फ्लड के बाद जो तरह-तरह की बीमारियां फैलने वाली है, जानलेवा बीमारियां फैलने वाली हैं, उससे कैसे बचाया जाए, उसके लिए यहां से एक मेडिकल टीम या दवाओं का इंतजाम हो । इन सारी चीजों की व्यवस्था केन्द्र सरकार के द्वारा कितनी हो सकती है, राज्य सरकार के समन्वय से कैसे हो सकती है, यह कोशिश होनी चाहिए । हमारी यही मांग होगी कि केन्द्र सरकार विशेसा रूप से उन तमाम राज्यों में जहां-जहां फ्लड आया है, वहां आगे भविष्य में उसको रोकने का काम किया जाए । बाढ़ से किसानों की रक्षा, खेतों की रक्षा, फसलों की रक्षा, आदि के लिए योजनाबध्द ढ़ंग से कार्य करने की आवश्यकता है । हर साल जो हम लोग औपचारिकता करते है, फ्लड का समय आता है , यहां सदन में बहस हो जाती है और हर आदमी अपनी बात, अपनी पीड़ा कह कर खामोश हो जाता है, यह इसका समाधान नही है । उपसभाध्यक्ष जी, बल्कि इस पर संजीदगी से एक योजना बनाने की जरूरत है कि किस तरह से हम बाढ़ को रोके, नही तो यह जो बर्बादी हो रही है, अगर इसी तरह की बर्बादी होती रही तो जो हम Infrastructure develop कर रहे है, आगे बढ़ा रहे हैं, सड़क, पुल, आदि जो छोटे-छोटे काम हम कर रहे है, गांव की विकास की बात कर रहे है, यह सब विफल हो जाएगा । इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन होगा कि इसके लिए एक योजना बनाकर देश को, पूरे राष्ट्र को इस बाढ़ से मुक्ति दिलाई जाए । बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोका जा सके, उसे कम से कम किया जाए । इस बात के लिए कदम उठाएं । धन्यवाद ।

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR (Karnataka): Sir, I thank you, very much for allowing me to participate in this discussion and put forward my views. Sir, as many of my senior colleagues in this House have said, and I join them in reiterating, the problem of floods in our country occurs almost every year and disrupts millions of lives and causes havoc and untold misery to those millions. Almost, every year, as a routine, we stand up and discuss floods and the Government responds with aid, grants and relief. A little late actually ever reaches the people affected by the floods and in many cases despite the Government aid and support, lives are irreparably damaged and destroyed. Sir, I will make my discussion in two parts. Firstly, I would like to summarise the impact of the floods and rains this year on my State, Karnataka and plead with the Central Government for financial support. Sir, my State has recorded very high rainfall this year, between June and August. The rainfall over the State between June and August has been the highest since 1870 and many districts including Koppal, Raichur, Bellary, Chitradurga, Belgaum, Bidar, Bagalkote, Bijapur, Hassan have recorded significantly high rainfall with many of these districts recording highest rain ever in the last 100 years. Sir, this has resulted in large inflows in major reservoirs and the huge release from these reservoirs have led to flooding, inundation and extensive damage to life, property, infrastructure, agriculture and crops. Sir, 43 lives have been lost and over 1,80,000 hectares of standing agricultural crops. and 21,000 hectares of horticultural crops have been damaged with total financial damages estimated to be over 1600 crores. This has been the cost of the

floods to our State. Our State has already submitted a First flood memorandum of Rs. 400 plus crores to the Government and the Central study team has visited the State and submitted its report to the Government. However, the Central Government has not released any fund under the NCCF and have only released Rs. 23.70 crores under the CRF. I would urge, through you, Sir, that Government of India release funds to my State as expeditiously as possible. Sir, coming to the second part of what I wish to say; many Members in the House have said 'we visit and re-visit the floods every year' and given our country's geography, its many rivers and basins and the increasing impact of global warming, floods will naturally occur every year. I also agree with many Members and I reiterate, that despite this almost annual event, we do not seem to have any long-term plan to address the problem of floods. I believe, it would be very appropriate in this the 60th year of our independence, that develop a longer term and sustainable strategy to address this debilitating tragedy that visits our country every year.

We owe it to our future generation that we leave behind some plan to address this annual problem. Sir, there are many variables - excessive rains, indiscriminate construction of dams on rivers, encroachment of river banks and basins, erosion of river banks and increasingly evident phenomenon of global warming - at play which creates this recurrent and annual occurrence of floods. So, there cannot be any simple or short-term solution to this.

Sir, I would like to, through you, make some suggestions to the Government as to what it can do for a long-term plan.

Firstly, the process of granting financial relief from the Centre to States should be completely restructured with the objective of ensuring speedier and more transparent financial resources to the affected State and its people. Removing, or, at least, reducing corruption in political partisanship during the process of allocating funds. One suggestion could be that the Government structure its various funds into one - Central Government guaranteed line of credit - and make them available to the States which are to be drawn during calamity in a transparent way and against the misuse of this line of credit. It is because, as we all know, there is a considerable misuse of Calamity Relief Fund.

Secondly - a few hon. Members have also touched this point - we must improve the process of forecasting of floods. Better forecasting can and should save lives, which, today, seem to be the collateral damage of our lack of will to develop a new approach to handle floods. Our Meteorological Department must be given more resources and its forecasting techniques and equipment must be upgraded. In addition, either the Meteorological Department or an appropriate agency of the Government, like IRSA, should look at using technology to remote sense and survey all our rivers, basins, especially in flood-prone regions. There is also a need to create a modern and high technology database that can be the basis of planning and forecasting of floods in the future. Sir, technology can and should be used to reduce the impact by some forecasting.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI UDAY PRATAP SINGH): Mr. Rajasekhar, how much time are you going to take? I know this is your maiden speech. Therefore, I don't want to interrupt you. But, please conclude.

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: Sir, I will take only one minute.

Thirdly, Sir, the issue of interlinking of rivers must be looked at. The previous NDA Government had planned an ambitious Inter-linking of Rivers and Basins Project. There are no signs of this project anymore. It is not clear if the present Government has shelved this Project or modified it or is just ignoring it. Either way, I believe, it deserves a re-look and some form of inter-linking, even if it is in a smaller and more targeted way, at certain geographies will serve to rebalance peaking water surges during flood season. I would urge the Government, through you, to attempt to create a political consensus around this issue of inter-linking of rivers.

Fourthly, the States must focus on the three issues - river bank encroachment, silting and erosion - which contribute significantly to floods. This is squarely in the territory of State concerned. The Government of India must develop a plan to work with the States to encourage and give incentives,. both in terms of funding and enforcement, to the States and Panchayats in this connection.

Finally, it is clear that our decades of abuse of environment and the on-going abuse of environment are causing global warming. The Government and, specifically, the Ministry of Environment and Forests, must get on top of this issue and give the nation a state of the factual report at the earliest which can be the basis for the country to start sensitising itself to the impact of abuse of environment on floods and other natural calamities. I would urge for a separate debate and discussion on this issue.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

To end, Sir, I reiterate, while the Government ensure the maximum effort to speed up relief and aids to the millions of displaced and flood-affected people, the Government must also, immediately, take the initiative to start the process of protecting our people from this annual occurrence of floods through a long-term and sustainable strategy, I urge all the political parties and hon. Members, who otherwise stand for the oppressed and downtrodden, to persuade the Government to launch this permanent long-term strategy to the whole issue of water and, in particular, flood prevention and protecting people from floods. I hope the Government will take the necessary steps in this regard. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, it is 5 o' clock. Now, statement by Minister. Mr. Baalu to make a statement...*(Interruptions)*...

श्री मंगनी लाल मंडल (बिहार) **:** उपसभापति महोदय, इस पर बहस कब होगी ?

श्री उपसभापति : यह बहस कंटीन्यू होगी। **...(व्यवधान)...**

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड) **:** सर, आप ऐसा नही कर सकते है। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : देखिए अहलुवलिया जी**...(व्यवधान)...**

श्री एस.एस. अहलुवालिया : सर, इंपॉर्टेंट यह है।

श्री उपसभापति : उसको अभी करेंगे ।**...(व्यवधान)...**

श्री एस.एस. अहलुवालिया : आप लोगों का क्लैरिफिकेशन का अधिकार छीन रहे हैं । **...(व्यवधान)...**

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, it is not fair. ...*(Interruptions)*... * Where is it written that the statement should be at 5 o'clock? ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : ऐसा कितने मौकों पर हुआ है । आप precedents देखिए ।**...(व्यवधान)...**

एक माननीय सदस्य : डिसकशन का क्या हुआ ?

श्री उपसभापति : यह कॉन्टीन्यू होगा ।**...(व्यवधान)...**

श्री एस.एस. अहलुवालिया : अगर आपने केवल खानापूर्ति करनी है तो करते रहिए ।**...(व्यवधान)...** मैंबर्स की जरूरत क्या हैं?**...(व्यवधान)...** आप स्टेटमेंट कराइए । यह सब क्या हैं?**...(व्यवधान)...** वे पढ़ क्या रहे हैं?**...(व्यवधान)...**

STATEMENTS BY MINISTER

Productivity-Linked-Reward for Port and Dock Workers/Employees

THE MINISTER OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI T.R. BAALU): Sir, The Port and Dock Workers of Major Ports and Dock Labour Boards are not covered by the Payment of Bonus Act, 1965. They are being paid Productivity-linked-Reward (PLR) instead. From 1994-95, they were paid PLR on the basis of Memorandum of Settlement dated 8.2.1996 between the Management of Major Port Trusts and Labour Federations of Port and Dock Workers under the Industrial Dispute Act, 1947. Under the scheme, the PLR was paid upto 2001-02.

A new PLR scheme was evolved by Indian Ports Association in consultation with Major Federations of Port and Dock Workers. In the new Scheme, there are three parameters *i.e.* Average Turn Round Time of ships with weightage of 30%, Average Ship berth day Output with weightage of 35% and unit cost of handling with weightage of 35%. Government approved on 8.2.2007 the new PLR Scheme for the period 2002-03 to 2009-10. A new settlement has also been signed between the Port Management and Federations on the new PLR Scheme on 10.4.2007. The joint reference earlier made to the National Tribunal, Mumbai on the question of payment of PLR on the basis of Port-wise productivity has also been withdrawn.

Now, the PLR for the year 2006-2007 is due for payment on or before 1-9-2007. The Indian Ports Association have made the computation of PLR for the year 2006-07 as per the agreed performance parameters and methodology and the PLR percentage is arrived at 21.38%, subject to the maximum ceiling of 20%. I have pleasure to inform the Hon'ble House that in accordance with the new settlement arrived at between the Port Management and the Major Federations, PLR for the year 2006-07 is being

---

* Expunged as ordered by the Chair.